

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहनलाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार

- अपीलार्थी

बनाम

बृजबासी पुत्र कांजीराम गुर्जर, निवासी होदाहेली थाना नादौती

- प्रत्यर्थी

अपील आर्म्स एक्ट

निर्णय

दिनांक-22.10.2019

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्री बृजबासी पुत्र कांजीराम गुर्जर, निवासी होदाहेली थाना नादौती जिला करौली ने जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली के आदेश न्याय/6730-77 दिनांक 16.09.2008 जिसके द्वारा श्री गुर्जर का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है, के विरुद्ध अपील संख्या 136/08 माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर में आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील में दिनांक 04.08.2009 को निर्णय पारित करते हुये श्री गुर्जर की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि श्री गुर्जर को पुनः साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः निर्णय पारित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर श्री गुर्जर को व्यक्तिगत तलब किया जाकर वकालतन/असालतन सुनवाई हेतु अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक करौली से रिपोर्ट तलब कर शामिल पत्रावली की गई।

बहस के दौरान श्री गुर्जर ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया कि शस्त्र को संबंधित थाने में जमा कराये जाने के समाचार पत्रों में प्रकाशित निर्देशों की जानकारी श्री गुर्जर को नहीं रही है और श्री गुर्जर को व्यक्तिगत सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। शस्त्र जमा कराने की सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण शस्त्र को जमा नहीं करवा पाया। अंत में श्री गुर्जर को जारी शस्त्र लाइसेन्स को बहाल करने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी प्रतिनिधि ने पक्ष प्रस्तुत करते हुये बताया कि तत्समय गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर किये जा रहे आन्दोलन को मध्येनजर रखते हुए जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को उनके शस्त्र सम्बन्धित थानों में जमा कराये जाने के आदेश प्रसारित किये गये। तत्समय की स्थिति में आलोच्य आदेश की प्रति की व्यक्तिगत तामील कराया जाना सम्भव नहीं था। इसलिये आदेश का प्रकाशन समाचार पत्रों के माध्यम से कराया। श्री गुर्जर द्वारा सूचना के उपरान्त शस्त्र जमा नहीं कराये जाने पर पुलिस अधीक्षक, करौली की अभिशंषा पर इनका शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है, जो विधिक प्रक्रिया के अनुसार सही है। अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त ही रखा जाने का कथन किया है।

पुलिस अधीक्षक, करौली ने रिपोर्ट क्रमांक ल-1/()श.अ. बहाली/डीएसबी /2019/10595 दिनांक 24.09.2019 से अवगत करवाया है कि श्री गुर्जर के विरुद्ध (1) मु.नं. 65/89 दिनांक 14.03.1989 धारा 147,148,323,448,325,427 आई.पी.सी. थाना नादौती में दर्ज हुआ जिसमें चार्जशीट नं. 39 दिनांक 31.03.1989 धारा 147,148,323,448, 325,427 आई.पी.सी. में पेश न्यायालय किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 22.06. 1998 को धारा 3 का लाभ व 400 रुपये का अर्थदण्ड देकर बरी किया गया। (2) मु.नं. 296/13 दिनांक 20.09.2013 धारा 376 आई.पी.सी. थाना करणी विहार जयपुर में पंजीबद्ध

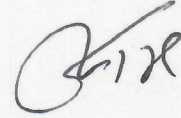
जिला कलक्टर
करौली

हुआ जिसमें चार्जशीट नं. 141 दिनांक 17.12.2014 धारा 376 आई.पी.सी. में पेश न्यायालय किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.07.2016 को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया। इसके साथ श्री गुर्जर को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल करने की अभिशंभा के साथ अपनी अनापत्ति प्रेषित की है।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय दिनांक 05.06.2008 को जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रों को निलंबित कर शस्त्र जमा करवाने बाबत आदेश जारी किया गया था। श्री गुर्जर द्वारा शस्त्र जमा नहीं करवाने की थानाधिकारी नादौती की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 16.09.2008 को श्री गुर्जर का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया था। तत्समय की स्थिति के अनुसार न तो सभी शस्त्र अनुज्ञापत्र धारकों पर व्यक्तिगत तामील करवाई जा सकती थी और ना ही व्यक्तिगत सुनवाई की जा सकती थी। श्री गुर्जर द्वारा तय समय सीमा में शस्त्र जमा नहीं कराया गया था। श्री गुर्जर द्वारा निर्धारित समय तक शस्त्र को थाने में जमा नहीं करवाने का कोई उचित कारण भी नहीं बताया गया। श्री गुर्जर के विरुद्ध मु.नं. 296/13 दिनांक 20.09.2013 धारा 376 आई.पी.सी. थाना करणी विहार जयपुर में पंजीबद्ध हुआ था जिसमें चार्जशीट नं. 141 दिनांक 17.12.2014 धारा 376 आई.पी.सी. में पेश न्यायालय की गई थी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.07.2016 को संदेह का लाभ दोषमुक्त किया गया था। अतः हम श्री गुर्जर का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया जाना उचित समझते हैं।

अतः श्री गुर्जर को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त किया जाता है। निर्णय सहित मूल पत्रावली न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट, करौली में भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(डॉ. मोहन लाल यादव)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
करौली